SAFALTA CLASS™

An Initiative by अमर उजाला

INDIAN

POLITY

BY – SUJEET BAJPAI SIR

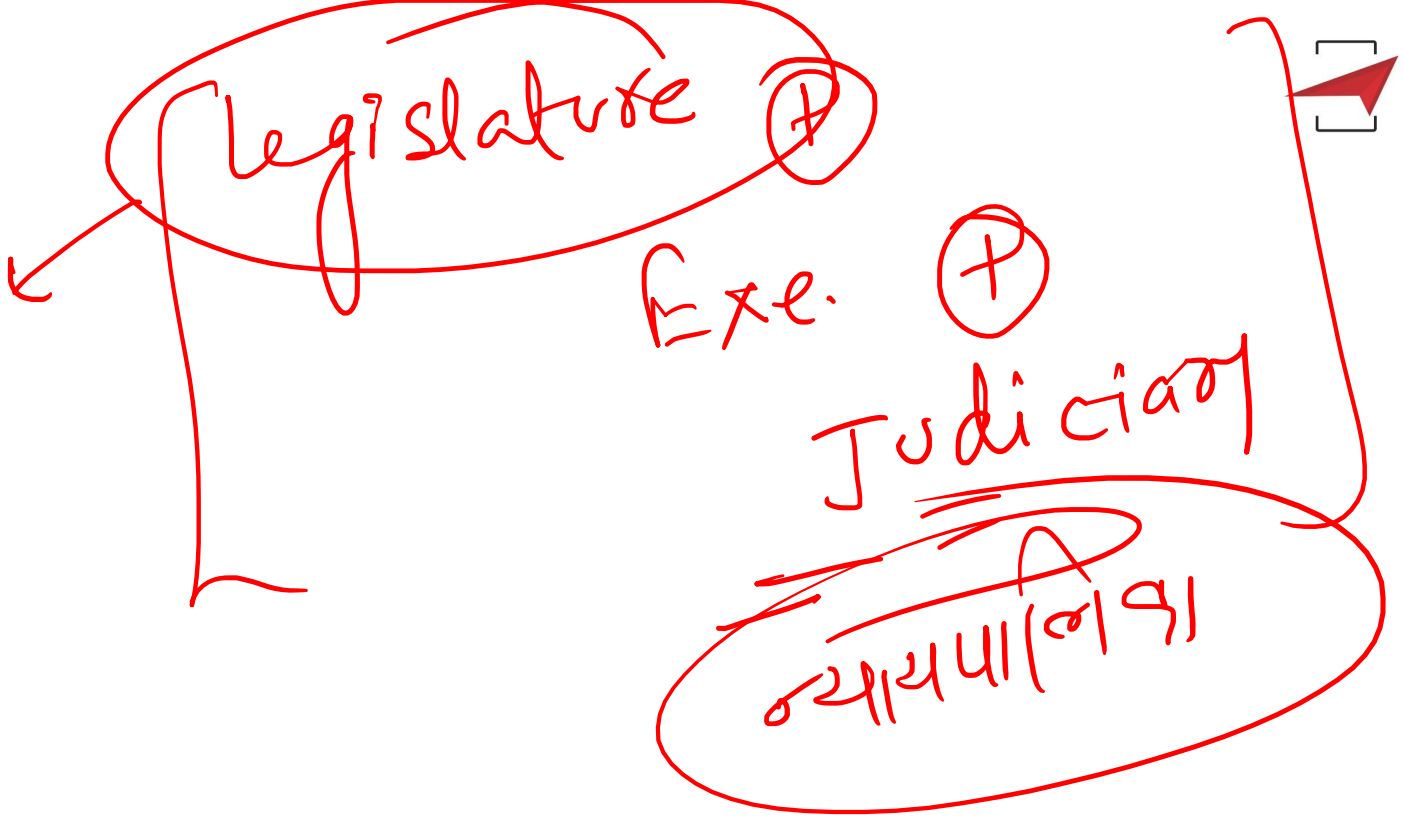

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

SAFALTA CLASS™

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Ripon रिपन = (Viceroy)

father of Local self rule

स्थानीय स्वशासन का पिता

place = Madras

oldest muni. of India.

नगरपालिका

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

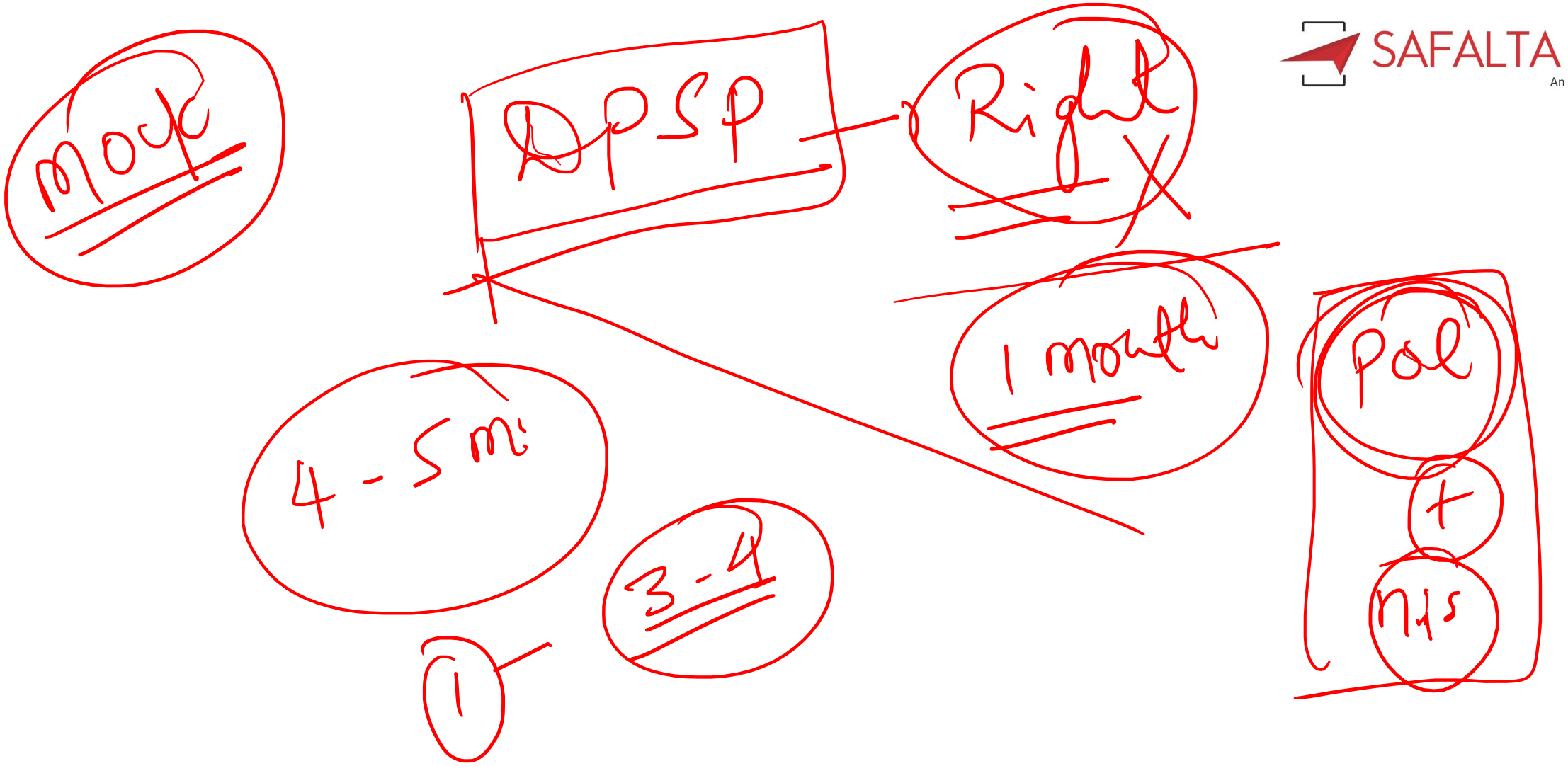

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

The term Panchayati Raj in India signifies the system of rural local self-government.

It has been established in all the states of India by the Acts of the state legislatures to build democracy at the grass root level.

It is entrusted with rural development. It was constitutionalised through the 73rd Constitutional Amendment Act of 1992.

भारत में पंचायती राज शब्द ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली का प्रतीक है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों द्वारा भारत के सभी राज्यों में इसकी स्थापना की गई है ।

इसका जिम्मा ग्रामीण विकास का जिम्मा है।

इसे 1992 के 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक बनाया गया था।

Evolution of Panchayati:

1. Raj Balwant Rai Mehta Committee (Jan-1957)

The committee submitted its report in November 1957 and recommended the establishment of a three-tier panchayati raj system—

gram panchayat at the village level,

panchayat samiti at the block level and

zila parishad at the district level.

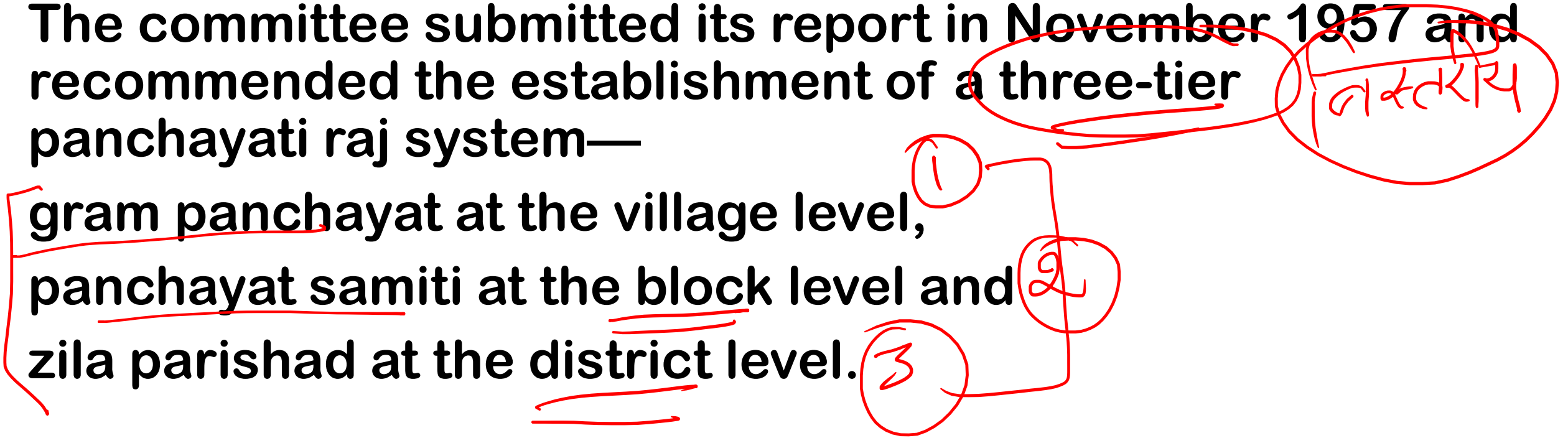

पंचायती राज का विकास:

1. राज बलवंत राय मेहता समिति (जनवरी-1957) समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की-

ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत,
ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और
जिला स्तर पर जिला परिषद।

Rajasthan was the first state to establish Panchayati Raj. The scheme was inaugurated by the prime minister on October 2, 1959, in Nagaur district.

Rajasthan was followed by Andhra Pradesh, which also adopted the system in 1959.

Thereafter, most of the states adopted the system.

पंचायती राज की स्थापना करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। इस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में किया था।

इसके बाद राजस्थान आंध्र प्रदेश ने भी 1959 में इस व्यवस्था को अपनाया। इसके बाद ज्यादातर राज्यों ने इस व्यवस्था को अपनाया।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Ashok Mehta Committee

In December 1977, the Janata Government appointed a committee on panchayati raj institutions under the chairmanship of Ashok Mehta.

It submitted its report in August 1978 and made 132 recommendations to revive and strengthen the declining panchayati raj system in the country.

अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं को लेकर एक समिति का का गठन किया गया ।

इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश में गिरती पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए 132 सिफारिशें कीं।

Ashok Mehta said The three-tier system of panchayati raj should be replaced by the two-tier system, that is, zila parishad at the district level, and below it, the mandal panchayat consisting of a group of villages.

अशोक मेहता ने कहा कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को बदलकर जिला स्तर पर जिला परिषद और उसके नीचे मंडल पंचायत गांवों का समूह बनाकर होनी चाहिए।

73rd Amendment Act of 1992

This bill finally emerged as the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 and came into force on 24 April, 1993.

1992 का 73 वां संशोधन अधिनियम

यह विधेयक अंतत 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के रूप में उभरा और 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

This act has added a new Part-IX to the Constitution of India.

This part is entitled as 'The Panchayats' and consists of provisions from Articles 243 to 243 O.

In addition, the act has also added a new Eleventh Schedule to the Constitution.

This schedule contains 29 functional items of the panchayats. It deals with Article 243-G.

इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया पार्ट-9 जोड़ा है ।

यह भाग पंचायतों के रूप में हकदार है और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के प्रावधान हैं।

इसके अलावा इस अधिनियम में संविधान में एक नई ग्यारहवीं अनुसूची भी जोड़ी गई है ।

इस शेड्यूल में पंचायतों की 29 फंक्शनल आइटम्स हैं। यह अनुच्छेद 243-जी से संबंधित है ।

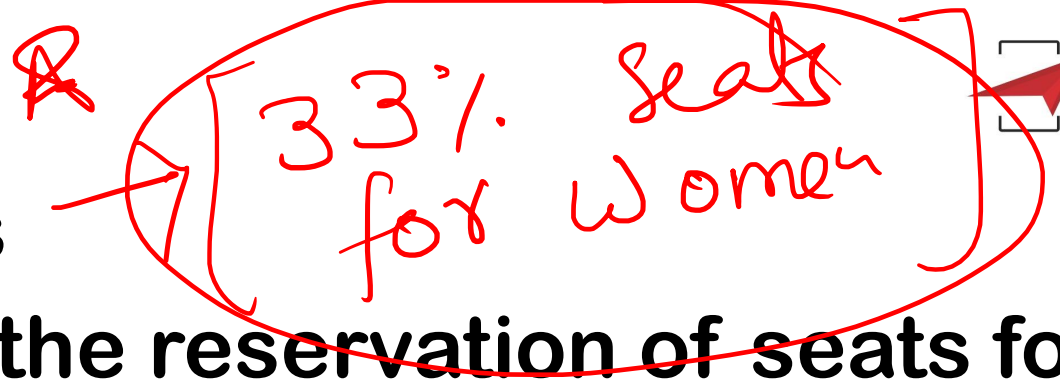

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Reservation of Seats

The act provides for the reservation of seats for scheduled castes and scheduled tribes in every panchayat (i.e., at all the three levels) in proportion of their population to the total population in the panchayat area.

Further, the state legislature shall provide for the reservation of offices of chairperson in the panchayat at the village or any other level for the SCs and STs.

सीटों का आरक्षण

इस अधिनियम में पंचायत क्षेत्र में कुल आबादी को अपनी आबादी के अनुपात में हर पंचायत (यानी तीनों स्तरों पर) में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण करने का प्रावधान है।

इसके अलावा राज्य विधानमंडल में पंचायत में अध्यक्ष के कार्यालयों को गांव में या किसी अन्य स्तर पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

The act provides for the reservation of not less than one-third of the total number of seats for women (including the number of seats reserved for women belonging the SCs and STs).

Further, not less than one-third of the total number of offices of chairpersons in the panchayats at each level shall be reserved for women.

इस अधिनियम में महिलाओं के लिए कुल सीटों की संख्या (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित) के एक तिहाई से कम आरक्षण का प्रावधान है।

इसके अलावा प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के कुल पदों की संख्या का एक तिहाई से भी कम महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा।

MUNICIPALITIES OF INDIA

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

74th Amendment Act of 1992 This Act has added a new Part IX-A to the Constitution of India.

This part is entitled as 'The Municipalities' and consists of provisions from Articles 243-P to 243-ZG.

In addition, the act has also added a new Twelfth Schedule to the Constitution.

This schedule contains eighteen functional items of municipalities. It deals with Article 243-W.

1992 के 74 वें संशोधन अधिनियम इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग नौवीं-ए जोड़ा है।

यह भाग नगर पालिकाओं के रूप में हकदार है और इसमें अनुच्छेद 243-पी से 243-ZG तक के प्रावधान शामिल हैं ।

इसके अलावा इस अधिनियम में संविधान में एक नई बारहवीं अनुसूची भी जोड़ी गई है ।

इस अनुसूची में नगरपालिकाओं के अठारह कार्यात्मक आइटम शामिल हैं। यह अनुच्छेद 243-डब्ल्यू से संबंधित है ।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Three Types of Municipalities

The act provides for the constitution of the following three types of municipalities in every state.

1. A nagar panchayat (by whatever name called) for a transitional area, that is, an area in transition from a rural area to an urban area.
2. A municipal council for a smaller urban area.
3. A municipal corporation for a larger urban area.

नगर पालिकाओं के तीन प्रकार इस अधिनियम में प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित तीन प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान है।

1. एक नगर पंचायत (जो भी नाम से कहा जाता है) एक संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए, यानी, एक ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में संक्रमण में एक क्षेत्र।
2. एक छोटे शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर परिषद।
3. एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर निगम।

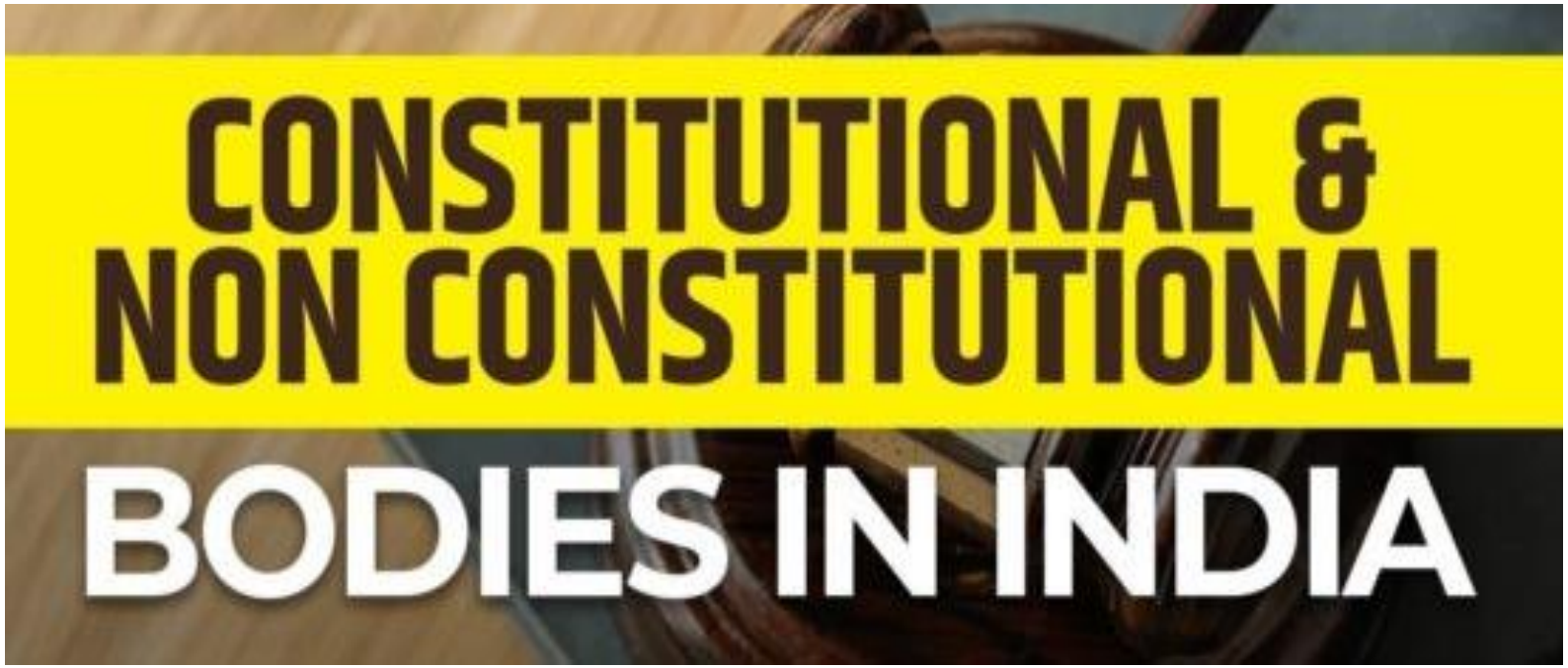
CONSTITUTIONAL &
NON CONSTITUTIONAL
BODIES IN INDIA

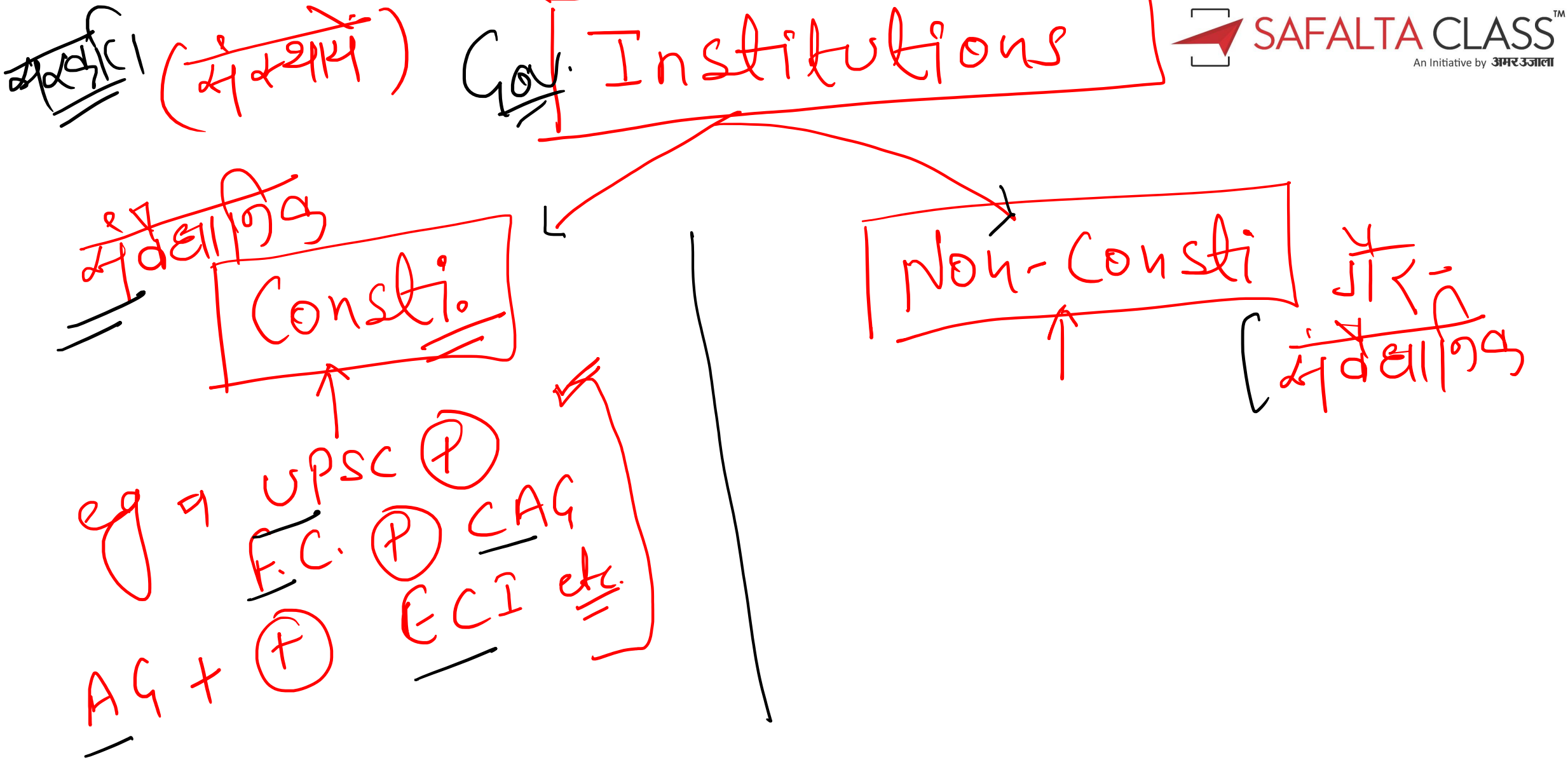

संस्कृति (संस्थायें) Govt. Institutions

SAFALTA CLASS
An Initiative by अमर उजाला

संवैधानिक — Consti.

Non-Consti — गैर-संवैधानिक

eg - UPSC (P)
F.C. (P) CAG
ECI etc.
AG + (P)

SAFALTA CLASS
An Initiative by अमर उजाला

Non - Consti

सांविधिक
(Statutory)
(By Parliament)
eg ⇒ SEBI (P)
NHAI (+)
TRAI (+)
IRDA

(Non - Stat.)
गैर - सांविधिक
By (Executive)
eg ⇒ (1) Planning Comm
||
NITI.
(2) NAC

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमरउजाला

केंद्रीय

मु. निर्वा. आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA (ECI)

(पंचायत ⓟ नगर पालिका)

राज्य निर्वाचन आयोग

The Election Commission is a permanent and an independent body established by the Constitution of India directly to ensure free and fair elections in the country.

चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सीधे भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है ।

Article 324 of the Constitution provides that the power of superintendence, direction and control of elections to parliament, state legislatures, the office of president of India and the office of vice-president of India shall be vested in the election commission.

संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान है कि संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति के पद और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनावों के अधीक्षण, दिशा और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होगी।

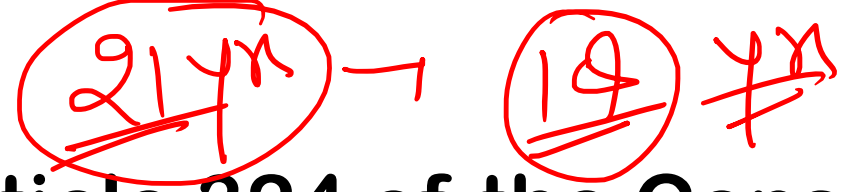

Composition Article 324 of the Constitution has made the following provisions with regard to the composition of election commission:

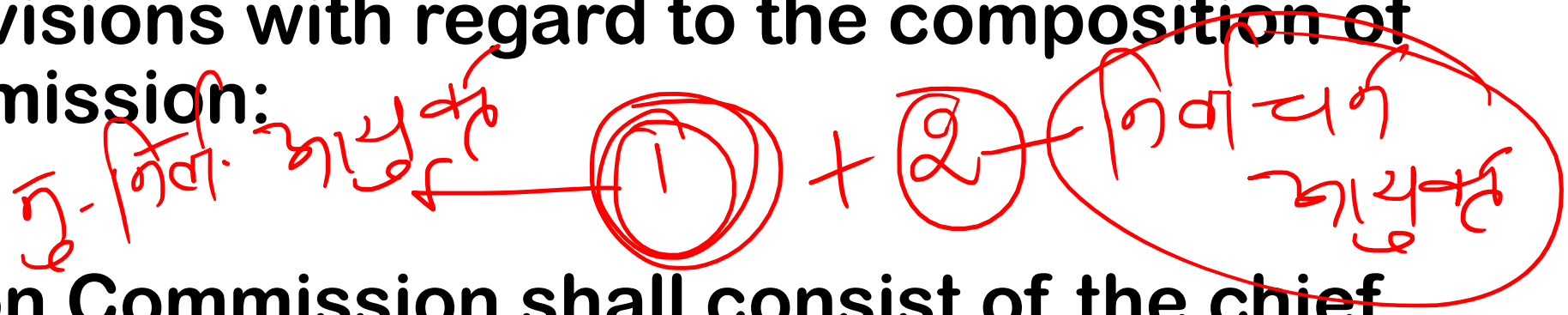

1. The Election Commission shall consist of the chief election commissioner and such number of other election commissioners, if any, as the president may from time to time fix.

संविधान के अधिनियम 324 में चुनाव आयोग के गठन के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

1. चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की इतनी संख्या शामिल होगी, यदि कोई हो, जैसा कि राष्ट्रपति समय-समय पर तय कर सकते हैं ।

2. The appointment of the chief election commissioner and other election commissioners shall be made by the president.

3. When any other election commissioner is so appointed, the chief election commissioner shall act as the chairman of the election commission.

2. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

3. जब किसी अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

4. The president may also appoint after consultation with the election commission such regional commissioners as he may consider necessary to assist the election commission.

5. The conditions of service and tenure of office of the election commissioners and the regional commissioners shall be determined by the president.

4. राष्ट्रपति चुनाव आयोग के साथ परामर्श के बाद ऐसे क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकते हैं क्योंकि वह चुनाव आयोग की सहायता के लिए आवश्यक विचार कर सकते हैं ।

5. चुनाव आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों के पद की सेवा और कार्यकाल की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी ।

Since its inception in 1950 and till 15 October 1989, the election commission functioned as a single member body consisting of the Chief Election Commissioner.

On 16 October 1989, the president appointed two more election commissioners to cope with the increased work of the election commission on account of lowering of the voting age from 21 to 18 years.

१९५० में अपनी स्थापना के बाद से और 15 अक्टूबर १९८९ तक चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर एक सदस्य निकाय के रूप में कार्य किया ।

16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करने के कारण चुनाव आयोग के बढ़े हुए काम से निपटने के लिए दो और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की।

Thereafter, the Election Commission functioned as a multimember body consisting of three election commissioners.

However, the two posts of election commissioners were abolished in January 1990 and the Election Commission was reverted to the earlier position.

इसके बाद चुनाव आयोग ने तीन चुनाव आयुक्तों से मिलकर एक बहुसदस्य निकाय के रूप में कार्य किया ।

हालांकि जनवरी 1990 में चुनाव आयुक्तों के दो पद समाप्त कर दिए गए थे और चुनाव आयोग को पहले की स्थिति में वापस कर दिया गया था।

Again in October 1993, the president appointed two more election commissioners.

Since then and till today, the Election Commission has been functioning as a multi-member body consisting of three election commissioners.

अक्टूबर १९९३ में फिर से राष्ट्रपति ने दो और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की ।

तब से लेकर आज तक चुनाव आयोग एक बहुसदसीय निकाय के रूप में काम कर रहा है जिसमें तीन चुनाव आयुक्त शामिल हैं ।

They hold office for a term of six years or until they attain the age of 65 years, whichever is earlier.

They can resign at any time or can also be removed before the expiry of their term.

वे छह वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करते हैं।

वे तरह-तरह के समय इस्तीफा दे सकते हैं या फिर उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले हटाया भी जा सकता है।

Article 324 of the Constitution has made the following provisions to safeguard and ensure the independent and impartial.

The chief election commissioner is provided with the security of tenure.

He cannot be removed from his office except in same manner and on the same grounds as a judge of the Supreme Court

संविधान के अनुच्छेद 324 में स्वतंत्र और निष्पक्ष की रक्षा और सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। उन्हें उसी तरीके से और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान आधार पर छोड़कर उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है ।

In other words, he can be removed by the president on the basis of a resolution passed to that effect by both the Houses of Parliament with special majority, either on the ground of proved misbehaviour or incapacity.

Thus, he does not hold his office till the pleasure of the president, though he is appointed by him.

दूसरे शब्दों में, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा विशेष बहुमत के साथ संसद के दोनों सदनों द्वारा इस आशय के पारित संकल्प के आधार पर हटाया जा सकता है, या तो साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर ।

इस प्रकार, वह राष्ट्रपति की खुशी तक अपना पद धारण नहीं करते हैं, हालांकि उनके द्वारा नियुक्त किया जाता है ।

सत्यमेव जयते

Finance Commission
Of India

Article 280 of the Constitution of India provides for a Finance Commission as a quasi judicial body.

It is constituted by the president of India every fifth year or at such earlier time as he considers necessary.

Composition

The Finance Commission consists of a chairman and four other members to be appointed by the president.

They hold office for such period as specified by the president in his order.

They are eligible for reappointment.

The chairman should be a person having experience in public affairs and the four other members should be selected from amongst the following:

1. A judge of high court or one qualified to be appointed as one.

2. A person who has specialised knowledge of finance and accounts of the government.

3. A person who has wide experience in financial matters and in administration.

4. A person who has special knowledge of economics.

Functions

The Finance Commission is required to make recommendations to the president of India on the following matters:

1. The distribution of the net proceeds of taxes to be shared between the Centre and the states, and the allocation between the states of the respective shares of such proceeds.

2. The principles that should govern the grants-in-aid to the states by the Centre (i.e., out of the consolidated fund of India).

3. The measures needed to augment the consolidated fund of a state to supplement the resources of the panchayats and the municipalities in the state on the basis of the recommendations made by the state finance commission.

4. Any other matter referred to it by the president in the interests of sound finance.

The commission submits its report to the president.

It must be clarified here that the recommendations made by the Finance Commission are only of advisory nature and hence, not binding on the government.

Source
Britain

नियंत्रक | महालेखा परीक्षक

The Constitution of India (Article 148) provides for an independent office of the Comptroller and Auditor General of India (CAG).

He is the head of the Indian Audit and Accounts Department.

He is the guardian of the public purse and controls the entire financial system of the country at both the levels—the Centre and the state.

Appointment and Term

The CAG is appointed by the president of India by a warrant under his hand and seal.

The CAG, before taking over his office, makes and subscribes before the president an oath.

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

He holds office for a period of six years or upto the age of 65 years, whichever is earlier.

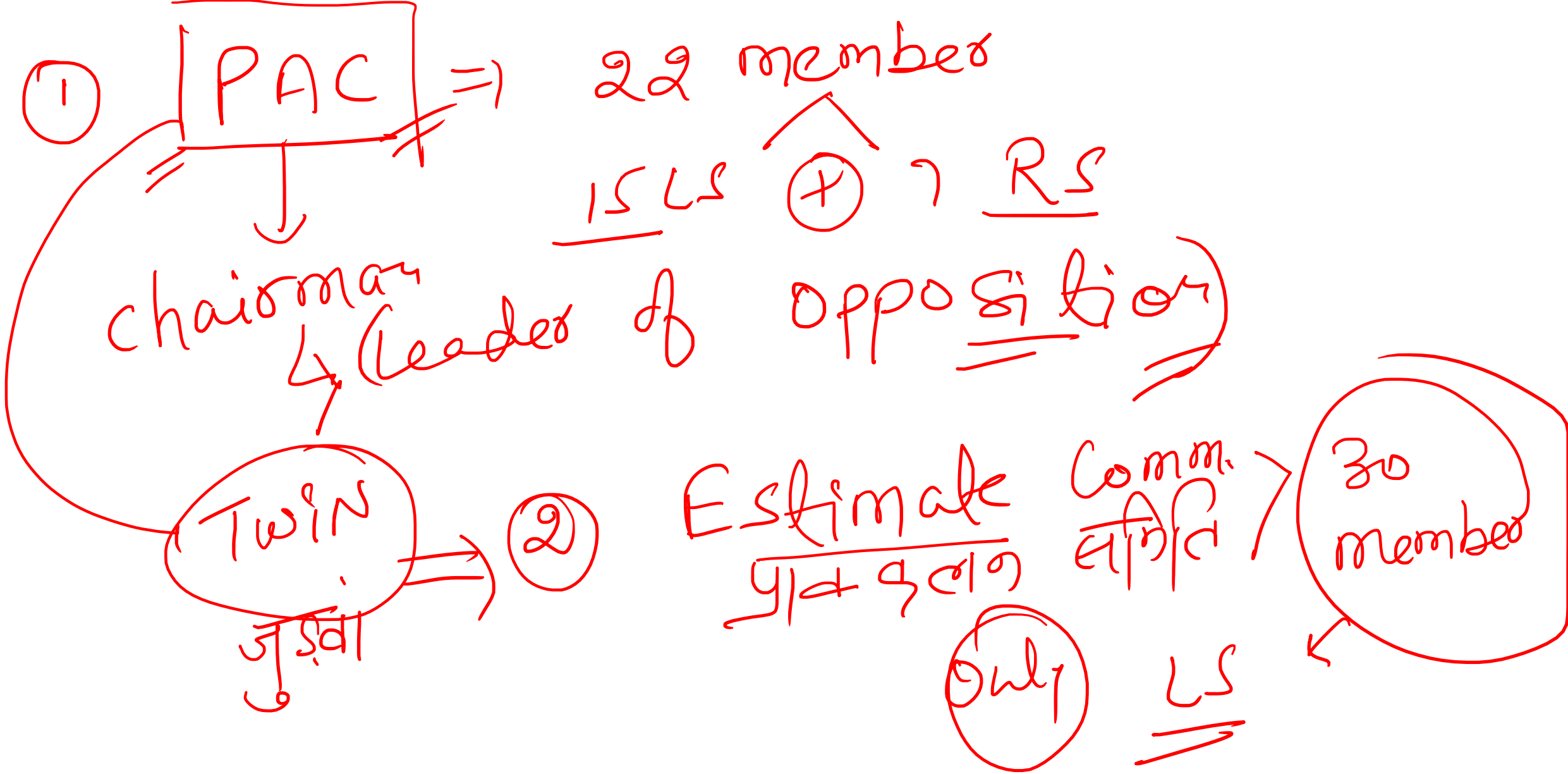

① PAC ⇒ 22 member

15 LS + 7 RS

chairman → (Leader of opposition)

TWIN (जुड़वा) → ② Estimate Comm. (प्राक्कलन समिति) → 30 member

Only LS

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमरउजाला

Highest law officer to gov.

Attorney-General Of India(Article-76)

भारत का महान्यायवादी

Cabinet Rank

Full Time Job ✗

Term ✗

The Constitution (Article 76) has provided for the office of the Attorney General for India.

He is the highest law officer in the country.

Appointment and Term

The Attorney General (AG) is appointed by the president.

He must be a person who is qualified to be appointed a judge of the Supreme Court.

In other words, he must be a citizen of India and he must have been a judge of some high court for five years or an advocate of some high court for ten years or an eminent jurist, in the opinion of the president.

However, the Attorney General is not a full-time counsel for the Government. He does not fall in the category of government servants. Further, he is not debarred from private legal practice.

Solicitor General of India In addition to the AG, there are other law officers of the Government of India.

They are the solicitor general of India and additional solicitor general of India. They assist the AG in the fulfilment of his official responsibilities.

It should be noted here that only the office of the AG is created by the Constitution.

In other words, Article 76 does not mention about the solicitor general and additional solicitor general.

AG can participate in meetings of parliament but can't vote.

UPSC
UNION PUBLIC
SERVICE
COMMISSION

Articles 315 to 323 in Part XIV of the Constitution contain elaborate provisions regarding the composition, appointment and removal of members along with the independence, powers and functions of the UPSC.

संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियों और कार्यों के साथ-साथ सदस्यों की संरचना, नियुक्ति और उन्हें हटाने के संबंध में विस्तृत प्रावधान हैं।

The UPSC consists of a chairman and other members appointed by the president of India.

The Constitution, without specifying the strength of the Commission has left the matter to the discretion of the president, who determines its composition.

यूपीएससी में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं ।

आयोग की ताकत निर्दिष्ट किए बिना संविधान ने इस मामले को राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया है, जो इसकी संरचना निर्धारित करता है ।

The chairman and members of the Commission hold office for a term of six years or until they attain the age of 65 years, whichever is earlier.

However, they can relinquish their offices at any time by addressing their resignation to the president.

They can also be removed before the expiry of their term by the president in the manner as provided in the Constitution.

आयोग के अध्यक्ष और सदस्य छह वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करते हैं। हालांकि, वे राष्ट्रपति को अपने इस्तीफे को संबोधित करके किसी भी समय अपने पद त्याग सकते हैं ।

संविधान में दिए गए तरीके से राष्ट्रपति द्वारा उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले उन्हें हटाया भी जा सकता है।

Removal

The President can remove the chairman or any other member of UPSC from the office under the following circumstances:

(a)If he is adjudged an insolvent (that is, has gone bankrupt);

(b) If he engages, during his term of office, in any paid employment outside the duties of his office;

हटाना राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकते हैं:

(क) अगर वह एक दिवालिया चुना है (यानी, दिवालिया हो गया है);

(ख) यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान, अपने कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी सशुल्क रोजगार में संलग्न है;

or (c) If he is, in the opinion of the president, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body.

In addition to these, the president can also remove the chairman or any other member of UPSC for misbehaviour.

या (ग) यदि वह राष्ट्रपति की राय में मन या शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है ।

इनके अलावा राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भी दुर्व्यवहार के लिए हटा सकते हैं।